ल.अं./49/एस.एल.बी.सी./३०४ 30.08.2023

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/ महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2023 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक दिनांक 16.08.2023 का कार्यवृत्त

कृपया हमारे पत्र संख्या ल.अं./49/एस.एल.बी.सी./291 दिनांक 18.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आप को राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2023 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था ।

उपरोक्त क्रम में उक्त बैठक का संशोधित कार्यवृत आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर पुनः प्रेषित है। कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(समीर रंजन पंडा)
महाप्रबन्धक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
फोन / Phone : 0522-6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677730 (CM), 6677721, 6677725
ई–मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2023 तिमाही की दिनांक 16.08.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2023 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 16.08.2023 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में श्री दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं डॉ बालू केंचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक,लखनऊ की सह-अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। इस बैठक में श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, एम एस एम ई, उत्तर प्रदेश शासन, श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि , उत्तर प्रदेश शासन, श्री अलोक कुमार, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र., श्री संजय कुमार डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ, श्री राजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), श्री समीर रंजन पंडा, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागो के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 26.06.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

मार्च 2023 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 26.06.2023 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./49/एसएलबीसी/224 दिनांक 15.07.2023 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

अपने स्वागत संबोधन में सर्वप्रथम **श्री राजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0)** ने मुख्य सचिव, उ प्र शासन का विशेष आभार व्यक्त करते हुए अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया।साथ ही श्री समीर रंजन पंडा, जिन्हे हाल ही मे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं लखनऊ अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा के पद पर नामित किया गया है, का सभा से परिचय कराया।

गत बैठक दिनांक 26.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत, उन्होंने प्रदेश में गत तिमाही के दौरान घटित महत्वपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया:-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही (जून 2023) के दौरान प्रदेश का कुल जमा रू 15.54 लाख करोड़ रहा है जो जून 2022 (रू 13.82 लाख करोड़) के तुलना में रू 1.72 लाख करोड़ अधिक रहा हैं। साथ ही जून 2023 में कुल अग्रिम रू 8.56 लाख करोड़ रहा है जिसमें जून 2022 (रू 7.37 लाख करोड़) के स्तर से रू 1.19 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल बैंकिंग व्यवसाय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश रू 24.11 लाख करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है।

- प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बना है जिससे बैंकों का ऋण प्रवाह मे भी बढ़ोत्तरी परिलक्षित हो रही है। जून 2023 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 55.07% रहा है जो जून 2022 के स्तर 53.37% से 1.70% की वृद्धि दर्शाता है। अवगत करना है कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको द्वारा ऋण जमानुपात बढ़ाये जाने हेतु समग्र रूप से कार्ययोजना बनाते हुए प्रयास किये जा रहे है। जून 2023 तिमाही मे प्रदेश में 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या घटकर -11- रह गई है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

- चालू वित्तीय वर्ष के जून 2023 तिमाही के दौरान वार्षिक ऋण योजनांतर्गत (Annual Credit Plan) आवंटित लक्ष्य रू 3,48,684 करोड़ के सापेक्ष रू 1,23,246 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 35.35% की उपलब्धि हासिल की गयी है। उन्होने बताया कि दिनांक 04.06.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता मे एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमे सभी जनपदो मे वार्षिक ऋण योजनांतर्गत एम एस एम ई सेक्टर मे लक्ष्यो को संशोधित करने के निर्देश दिये गए थे। अग्रणी जनपदो से प्राप्त संशोधित लक्ष्यो को समाहित करते हुए दिनांक 26.06.2023 को वार्षिक ऋण योजना 2023-24 का विमोचन किया गया।

- प्रधानमंत्री जन धन योजनांतर्गत प्रदेश में अभी तक कुल 8.80 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमे से जून 2023 तिमाही के दौरान 13 लाख जन धन खाते खोले गये है।

- चालू वित्तीय वर्ष के जून 2023 तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना यथा पी.एम.एस.बी.वाई. (PMSBY) एवं पी.एम.जे.जी.बी.वाई. (PMJJY) योजनांतर्गत क्रमश: 10.83 लाख एवं 28.41 लाख नामांकन किये गये है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत कुल 4.98 करोड़ नामांकन के साथ हमारा प्रदेश पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1.75 करोड़ नामांकन के साथ हम भारतवर्ष में द्वितीय स्थान पर है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश मे दिनांक 01.04.2023 से 31.07.2023 तक एक संतीप्तीकरण अभियान का भी आयोजन किया गया।

- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित लक्ष्य 15,83,950 के सापेक्ष 4,78,348 नामांकन किये जा चुके है जो 30% की उपलब्धि दर्शाता है।हमारे प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु "AWARD OF PAR EXCELLENCE" प्राप्त हुआ है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रदेश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ करने हेतु संतृप्तीकरण अभियान चलाया जा रहे है जिसके तृतीय चरण हेतु हमारे प्रदेश के 8 नये जनपदों यथा फतेहपुर (बैंक ऑफ़ बड़ोड़ा), कन्नौज (बैंक ऑफ़ इंडिया, अमरोहा (केनरा बैंक), वाराणसी (यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया), शामली (पंजाब नेशनल बैंक), महाराजगंज (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया), देवरिया (सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया) तथा बहराइच (इंडियन बैंक) को चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एस.एल.बी.सी. की उप-समिति द्वारा की जा रही है।निश्चय ही समस्त बैंकों के समग्र प्रयास से हम इस लक्ष्य को भी पूर्व की भांति हासिल कर लेंगे।

अंत मे उन्होने पुन: मुख्य सचिव महोदय का बैठक मे उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया एवं अन्य सहभागियों की उपस्थिति हेतु धन्यवाद दिया।

डॉ बालू केंचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक,लखनऊ ने अपने संबोधन मे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, का अभिवादन करते हुए सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार, समस्त बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानो के अधिकारीगणों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। डॉ बालू केंचप्पा ने निम्न मुद्दो की ओर समस्त सभाजनों का ध्यानाकर्षण किया :

- देश में सर्वाधिक Unclaimed Deposits (रु 4,580 करोड़) उत्तर प्रदेश में है जो कि एक चिंता का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर आमजनमानस को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहकों को Unclaimed Deposits का दावा करने के लिए संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "100 days

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow अंचल कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

100 pays" अभियान की शुरूआत की गई है। उन्होने इस अभियान के दौरान बैंकों को 100 दिनों के भीतर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 Unclaimed Deposits को चिन्हित कर जमाकर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाने का आहवाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया कि प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के Unclaimed Deposit लंबित है| | उन्होने समस्त बैंको को निर्देशित किया कि ऐसे खातो की सूची निकालकर संबन्धित सरकारी विभाग से समन्वय स्थापित कर लंबित Unclaimed Deposit का क्लेम कराना सुनिश्चित करें|

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रदेश मे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ करने एवं पूर्णत: डिजटलीकृत करने हेतु तृतीत चरण हेतु -8- जनपद चिन्हित किए गए है। उन्होने समस्त बैंको को निर्देशित किया कि उक्त -8- जनपदो मे आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक प्रगति मे शेष बचे Gap का 30% एवं 70% क्रमश: सितम्बर' 2023 एवं दिसंबर' 2023 तक प्राप्त करते हुए शत प्रतिशत हासिल करना सुनिश्चित करे| साथ ही उन्होने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदो को 100% डीजटलीकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। समस्त बैंको को प्रदेश के समस्त जनपदो को पूर्णत: डीजटलीकृत किए जाने का आहवाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- ऋण जमा अनुपात पर चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार कि नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में ऋण प्रवाह में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके परिणाम स्वरुप जून 2023 में CD Ratio 55.07% रहा। ऐसे जनपद जहां पर्याप्त संभावनाएं व्याप्त है, विशेषकर 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपद, मे वित्त की पहचान कर उसे और बढ़ाने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक)

- वित्तीय सेवाओं को आमजनमानस तक पहुंचाने में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि उनके संचालन की नियमित आधार पर निगरानी की जाए। बैंको द्वारा Inactive BCs को Active करना; क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक एवं एस एल बी सी को बी सी की रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री एस. के. डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Regional Office (Lucknow Zone), Lucknow क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

- भारतीय रिज़र्व बैंक के Bank Lending Survey 2023-24, के अनुसार देश में ऋण प्रवाह में सकारात्मकता का माहौल दर्ज किया गया है।

- उत्तर प्रदेश में ऋण की कमी वाले (Credit Starved) 22 जनपद हैं, जिनमें से 11 जनपदो का ऋण जमा अनुपात अभी भी 40% से कम है। इन जनपदो में ऋण वृद्धि के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

- प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत जून 2023 तिमाही तक लगभग 32% लक्ष्य प्राप्त हो चुके है। योजनांतर्गत कोपरेटिव बैंको की स्थिति/ प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए बैंको द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने हेतु आग्रह किया।

(कार्यवाही: कोपरेटिव बैंक)

- प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा "**उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था**" का राज्य बनाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने हेतु सभी बैंकर्स से आहवाहन किया|

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु व्यापक कार्य किया जा रहा है।सभी बैंकों को इसका लाभ उठाते हुए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत Term Lending बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

- Green Financing को बढ़ावा देते हुए समस्त बैंको से Organic Farming, solar energy Pumps, Wind Mills, Bio Gas Plants इत्यादि मे ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु आहवाहन किया।

- देश में क्रेडिट - GDP अनुपात 50% है, जबकी प्रदेश का अनुपात 38% है, जिसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

श्री अमित मोहन प्रसाद, आई ए एस, अपर मुख्य सचिव, एम एस एम ई, उत्तर प्रदेश शासन, ने अपने सम्बोधन में अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं को सभा के समक्ष रखा :

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर 17 सितम्बर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर प्रदेश में ₹ 30,000 करोड़ के ऋण वितरण का एक वृहद् कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।इस कार्यक्रम की सफलता एवं सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त बैंको द्वारा सम्मलित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है ।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 21-25 सितम्बर के मध्य Greater Noida में "U.P. International Trade Show" का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसका उद्घाटन हमारे देश की महामहीम राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया जाना अपेक्षित है।सभी बैंको से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम मे अपने बैंक का स्टाल लगाकर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow अंचल कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

- विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत प्रगति समीक्षा पर चर्चा कराते हुए बताया कि योजनाओ के अंतर्गत प्राइवेट बैंको की स्थिति संतोषजनक नही है।प्रदेश के प्राइवेट बैंको को सरकार प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत और अधिक प्रयास करे जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: प्राइवेट बैंक)

श्री देवेश चतुर्वेदी, आई ए एस, अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश मे बैंको द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिसूचित फसलों पर प्रति किसान एक किसान क्रेडिट दिए जाने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जिससे एक किसान के पास एक ही किसान क्रेडिट कार्ड हो।

- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि योजनांतर्गत 9% ब्याज दर पर सबसिडी प्रदान किए जाने का प्रावधान है।चूंकि बैंको द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी Repo Rate पर निर्भर करती है। नोडल एजेंसी से अनुरोध है कि योजनांतर्गत ब्याज दर को Repo Rate के साथ allign किया जाये ताकि योजना का लाभ पात्र लोगो को मिल सकें।

श्री दीपक कुमार, आई ए एस, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के वित्तीय मानको पर विस्तार से चर्चा करते हुए संतोष व्यक्त किया।

श्री अलोक कुमार, आई ए एस, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश के ऋण जमानुपात पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि मार्च 2024 तक ऋण जमा अनुपात को 60% तक के स्तर तक पहुंचाए जाने हेतु समस्त बैंको द्वारा समग्र रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे वार्षिक ऋण योजनांतर्गत 102% उपलब्धि पर समस्त बैंको को बधाई दी।

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को वर्ष में -2- बार फ्री गैस सिलंडर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि योजना सफल क्रियान्वन हेतु सभी खाता धारको के खातो मे आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

BANK OF BARODA
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
उ० प्र०
Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow
कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ०प्र० ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, का बैठक में पधारने हेतु आभार व्यक्त करते हुए सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन किया।उन्होंने अपने सम्बोधन मे निम्न बिन्दुओ को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया:

- प्रदेश मे कार्यरत समस्त बैंको के सम्मिलित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 102% की उपलब्धि हासिल की गई।

- माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में -500- Aspirational Block की घोषणा की थी जिसमे से -100- Block उत्तर प्रदेश से संबन्धित है।100 ब्लॉक में से 76 ब्लॉक मे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण का औसत प्रदेश औसत से कम है, जिसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

- प्रदेश मे -11- जनपदो का ऋण जमानुपात 40% से कम है जिसे दिसंबर 2023 तक 40% के स्तर से अधिक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।सभी अग्रणी बैंको से अनुरोध है कि इन जनपदो मे अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन करते हुए जनपद मे विशेष ऋण शिविर एवं रोजगार मेला का आयोजन किया जाये ताकि इन जनपदो का ऋण जमानुपात 40% के पार पहुंचाए जाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं समस्त बैंक)

- अन्तर्राजिय परिषद्, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में शेष -243- बैंक शाखा रहित केन्द्रों पर शाखा खोलने पर चर्चा करते हुए शेष -243- केन्द्रों पर IPPB/कोआपरेटिव बैंक की शाखाये खोलने हेतु आहवाहन किया।

(कार्यवाही: IPPB/कोआपरेटिव बैंक)

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत Animal Husbandry तथा Fisheries क्षेत्र के कृषको को केसीसी जारी किए जाने की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया।उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि Animal Husbandry तथा Fisheries को योजना के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक संख्या मे के सी सी जारी किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- बैंको द्वारा ऋण प्रवाह बढाने हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों विशेषकर क्रेडिट आउटरीच कैम्पों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकों की प्रशंसा की।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow अंचल कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

- बैंकों में बढ़ते हुए NPA की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जनपदो के जिलाधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वसूली मे सहयोग प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने से अवगत कराया।

श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई ए एस, मुख्य सचिव, उ प्र शासन ने अपने अध्यक्षीय संबोधन मे सभा मे उपस्थित प्रदेश सरकार एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगण को समीक्षा बैठक मे निम्नवत संबोधित किया :

- सर्वप्रथम बैठक के दौरान विभिन्न एजेंडा बिंदुओ पर हुई सार्थक चर्चा की सराहना की।उन्होने जुलाई माह में जनपद वाराणसी मे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति मे आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम मे प्रदेश के 1.39 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पी एम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के लिए समस्त बैंकर्स को बधाई दी|

- उन्होने बताया कि पी एम स्वनिधि योजनान्तर्गत अभी भी 80,000 से अधिक आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित है।साथ ही यह भी बताया कि प्रदेश मे 200 नए ULBs का निर्माण/ विस्तार हुआ है जो शहर के वृहद क्षेत्र को कवर करेंगी तथा जिसमे नए स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया जाना भी प्रस्तावित है।उन्होने प्रदेश में पी एम स्वनिधि योजनान्तर्गत 114% की उपलब्धि हासिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा योजनान्तर्गत आवंटित संशोधित लक्ष्यो को दिसंबर 2023 तक पूर्ण किए जाने हेतु समस्त बैंको को निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- उन्होने बताया कि एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा एक नई बीमा योजना की शुरूआत की गई है जो मुख्यत: एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋणी को बीमा प्रदान करेगी।इस योजना से प्रदेश के समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को भी कवर किया जाना है।सभी स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु निर्देशित किया।

- उन्होने वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के अंतर्गत प्रथम तिमाही मे ही एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत रू 67126 करोड़ (66%) का ऋण वितरण किए जाने पर समस्त बैंकर्स साथियो को बधाई दी।साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एम एस एम ई सेक्टर को रू 3 लाख करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य प्रदान किया।

- उन्होने प्रदेश के ऋण जमानुपात का पुनर्मूल्यांकन करते हुए बताया कि ऋण जमानुपात प्रारम्भ से ही प्रदेश के जमा एवं अग्रिम हेतु एक संकेतक रहा है।ऋण जमानुपात से ही प्रदेश का वास्तविक जमा तथा अग्रिम परिलक्षित होता है।उन्होने बताया कि हमारे प्रदेश मे पर्याप्त संभावनाए है जिनसे प्रदेश के जमा मे निश्चित रूप से वृद्धि होगी।साथ ही हाल ही मे आयोजित Global Investors Summit से भी विभिन्न क्षेत्रो मे अग्रिम की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, साथ ही नवंबर माह से पूर्व आयोजित होने वाली First Ground Breaking Ceremony मे भी लगभग रू 10 लाख करोड़ के ऋण प्रदान किए जाने की संभावनाए है जिससे निश्चय ही हमारे प्रदेश का जमा के साथ साथ अग्रिम मे भी बढ़ौत्तरी होगी।

- उन्होने सर्वप्रथम 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदो को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन जनपदों मे निवेश को बढ़ाते हुए ऋण जमा अनुपात 40% से अधिक किए जाने पर ज़ोर दिया।40% से कम ऋण जमानुपात वाले -11- जनपदो के अग्रणी बैंको से अनुरोध किया कि इन जनपदो मे एक विशेष वृहद ऋण शिविर का आयोजन किया जाये ताकि जनपदो का ऋण जमानुपात

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० Zonal Office (Lucknow Zone), Lucknow अंचल कार्यालय (लखनऊ अंचल), लखनऊ

शीघ्र 40% के मानक स्तर को पार कर जाये ।साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 मे प्रदेश के ऋण जमानुपात को 60% से अधिक पहुचाएं जाने हेतु समस्त बैंकर्स द्वारा सम्मिलित रूप से विशेष प्रयास किए जाने का अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी बैंक एवं समस्त बैंक)

- उन्होने प्रदेश मे डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बढ़ाए जाने पर ज़ोर देते हुए बैंको से अनुरोध किया कि समस्त ग्राहको को कम से कम एक डिजिटल मोड यथा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इन्टरनेट बैंकिंग एवं यू पी आई से अवश्य जोड़ा जाये, साथ ही समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को यू पी आई प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाये |

- उन्होने बताया कि प्रदेश मे पायलट आधार पर -4- जनपदो मे किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल माध्यम से जारी किए जाने हेतु चिन्हित किया गया था| यह प्रयास सफल रहा है। उन्होने समस्त बैंको को निर्देशित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि किसानो को आसानी से कम समय मे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जा सके ।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- उन्होने सभी पात्र किसानो जिन्हे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है, को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- बैठक के दौरान उन्होने बताया कि बुंदेलखंड, पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश मे ऋण प्रवाह की स्थिति मे सुधार हेतु एक उप समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता है। उक्त समिति द्वारा इन क्षेत्रो मे ऋण प्रवाह की प्रगति पर चर्चा किया जाना अपेक्षित है|

(कार्यवाही: एस एल बी सी विभाग)

बैठक के अंत में श्री शरद एस. चंडक, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैठक मे समय देने के लिए श्री दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का विशेष आभार व्यक्त किया गया तथा उनके अमूल्य मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया।उन्होने प्रदेश सरकार के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगणो एवं बैंको से पधारे अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक सम्पन्न की जा सकी।

****